Thank you, P. Wilson *ji*. Now, Shri Muzibulla Khan. Dr. Sasmit Patra will associate.

Demand for Special Category Status to the State of Odisha

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, मैं ओडिशा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के पक्ष में अपनी बात रखना चाहता हूँ। भारत की प्रगति तभी हो सकती है, जब राज्यों का विकास होगा। जब राज्यों का विकास होगा, तभी 'सबका साथ, सबका विकास' का जो नारा दिया गया है, वह फुलफिल हो सकता है। मेरे नेता नवीन पटनायक जी के बारे में भारतवर्ष के सारे लोग जानते हैं कि वे कितनी सिम्प्लिसिटी से रहते हैं और कितने सीधे-साधे इंसान हैं। उन्होंने चार जोड़ी कुर्ता-पायजामा और चार जोड़ी हवाई चप्पल से 25 साल ओडिशा राज्य में शासन किया। जब वे मुख्य मंत्री थे, तो वे बार-बार केन्द्र सरकार को ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में चिट्ठी लिखते थे। हमारे संसद सदस्य ने लोक सभा तथा राज्य सभा में इस विषय को उठाया, लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक ओडिशा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। हम समझते हैं कि इसके लिए एक तय क्राइटीरिया है, कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं, लेकिन किसी की भलाई के लिए इस कानून को बदला जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है। हमारे राज्य में 22 प्रतिशत ट्राइबल इलाका है, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। यह बैकवर्ड एरिया है और यह टूरिज़्म के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है, प्रभु लिंगराज जी का मंदिर है, कोणार्क टेम्पल जैसा फेमस टेम्पल है, इसलिए यह टूरिज़्म के लिए भी जाना जाता है। सर, हमारे ओडिशा में 480 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है ,जिसके कारण हमारे राज्य को बार-बार तूफान झेलना पड़ता है। महोदय ,इस कोस्टल बेल्ट में हमारे सात जिले आते हैं और वे हैं - गंजम ,खोरधा ,पुरी ,केंद्रपाड़ा ,जगतसिंहपुर ,भद्रक और बालासोर। जब 1999 में सुपर साइक्लोन आया था ,तब 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थीं और 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे ,जिन्होंने अपने मां-बाप को खो दिया था। वर्ष 2000 में जब मेरे नेता नवीन पटनायक जी ओडिशा के मुख्य मंत्री बने और ओडिशा का शासन अपने हाथों में लिया ,तब उन्होंने इस बात के लिए कोशिश की कि साइक्लोन से कैसा निपटना है। सर ,वहाँ हर साल साइक्लोन आता है ,लेकिन मैं यहाँ कुछ प्रमुख साइक्लोन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। फाइलिन 2013 में आया था ,हुदहुद 2014 में आया था ,तितली 2018 में आया था और फनी 2019 में आया था। सर ,आप जानते हैं कि नवीन बाबू हर वक्त ज़ीरो कैजुअल्टी के मामले में नंबर वन हैं और देश तो क्या ,विदेश के लोगों से भी उनको इस बात के लिए धन्यवाद मिला है कि वे ज़ीरो कैजुअल्टी में आगे बढ़ते हैं। ...(**समय की घंटी**)...सर ,यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष ,नड्डा जी बैठे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

श्री मुजीबुल्ला खान : सर, मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। Time is over. अब आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। माननीय डा. सस्मित पात्रा जी, आप एसोसिएट करें।

श्री मुजीबुल्ला खान : *

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I am associating. Can I take ten seconds to make a point?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please associate only.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I associate. I associate myself with this matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following Members also associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Muzibulla Khan: Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), and Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh).

Now Shri Golla Baburao, 'Demand to implement a comprehensive National Coastal Tourism Development Policy in the country'.

Demand to implement a comprehensive National Coastal Tourism Development Policy in the country

SHRI GOLLA BABURAO (Andhra Pradesh): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Sir, I wish to bring a very important and innovative idea to the notice of the Union Government. Now, in entire India, more than 9,700 kilometres coastline is there, and, especially, in our Andhra Pradesh, 970 kilometres coastline is there. I am happy; but so far, the Union Government and the State Governments are developing some tourist-base for the coastal line. But, in fact, we can develop a comprehensive policy to develop the entire beach coastal line in almost all the States, from Gujarat to West Bengal, the entire coastline. What I request the Union Government is to identify as many beaches as possible and start the resorts, hotels and other recreational clubs. Apart from this, what I request the Union Government and the State Governments is to kindly start the actuaries and also some other basic infrastructural facilities for all the coastal lines. We can earn a lot of foreign exchange and we can also especially develop the fishery communities which

* Not recorded